[2008] 17 एस. सी. आर. 548

बिहार राज्य वित्तीय निगम

बनाम

एम/एस. छोटानापुर खनिज और अन्य

(सिविल अपील संख्या 7253 of 2008)

12 दिसंबर, 2008

[एस.बी. सिन्हा और सीरियाई जोसेफ,

न्यायमूर्तिगण]

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951- धारा 29 और 30 – अंतर्गत शक्ति - दायरा - आयोजितः केवल उन संपत्तियों के संबंध में प्रयोग की जाने वाली शक्ति जो गिरवी रखी गई थीं - संपत्ति की बिक्री, जो बंधक का हिस्सा नहीं है, अवैध है और अधिकार क्षेत्र के बिना है - वित्तीय निगम इस तरह की कार्रवाई से हुए नुकसान के लिए हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कारखाना स्थापित करने के लिए अपीलार्थी निगम से ऋण लिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 बंधक पट्टा निगम के साथ कारखाने की भूमि के एक टुकड़े पर

अधिकार रखता है। कारखाना स्थापित किया गया। निगम ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 और 30 के संदर्भ में कार्यवाही शुरू की। निगम ने कारखाना परिसर प्रत्यर्थी संख्या. 2 को बेच दिया। प्रत्यर्थी नंबर. 1 ने निगम के खिलाफ हर्जाने के लिए एक मुकदमा दायर किया जिसमें कहा गया था कि निगम ने अन्य संपत्तियों को भी बेचा जो बंधक का विषय नहीं थे, और विभिन्न संपत्तियों को प्रत्यर्थी नंबर. 3- बैंक के साथ उससे लिए गए ऋण के खिलाफ हाइपोथेकेटेड किया गया था। प्रतिवादी नंबर. 1 ने अनुसूची - क संपत्ति के लिए हर्जाने का दावा किया था। वाद की क्षतिपूर्ति के माध्यम से, अनुसूची ख, ग और घ संपत्तियों के संबंध में हर्जाने का भी दावा किया। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया। निचली अदालत के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी की थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहाः

अभिनिर्धारित: 1. वित्तीय निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29 और 30 के अधीन निगम में निहित वैधानिक शक्ति का

प्रयोग केवल उन संपत्तियों के संबंध में किया जाना चाहिए जिन्हें गिरवी रखा गया था। अपीलार्थी को ऐसी कोई संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं था जो बंधक विलेख का विषय न हो। उस ओर से की गई किसी भी कार्रवाई को पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाना चाहिए। इसलिए, याचिकाकर्ता था जैसा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा राय दी गई थी, नुकसान के भुगतान के लिए उत्तरदायी। 8 [अनुच्छेद 17 और 18] [558-छ; 559-ग-घ] ओर्मी टेक्सटाइल्स और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 2008 (5) धारा 194, इस केस के फैसले पर भरोसा किया गया था।

2. अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष संशोधित वाद प्रस्तुत नहीं किया है। अदालत को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है कि वाद की ख, ग और घ अनुसूचियाँ किस बारे में थीं। बार में यह स्वीकार किया जाता है कि वादी की अनुसूची क में उल्लिखित चल संपत्तियां प्रत्यर्थी सं. 3 - बैंक के पास गिरवी रखी गई थी। इसके अलावा इस बात से इनकार या विवाद नहीं किया गया है कि प्रतिवादी नं - 3 -बैंक ने अपने बकाये की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। बैंक को दी गई चल संपत्तियों की वसूली

नहीं की गई थी और चूंकि इसे हटाने की अनुमति थी, इसलिए डिक्रीटल राशि रुपये 1, 87, 635. 24 की राशि के भुगतान के लिए अनुरोध के संबंध में हर्जाने के रूप में प्रत्यर्थी सं. 3. को डिक्रिटल राशि का भुगतान अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3 को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा निर्देशित ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश हुआ था। [अनुच्छेद 19,20 और 21] [559-ड; 560-ग-ड]

मामला कानून संदर्भः

(2008) 5 एससीसी 194 पर निर्भर था अनुच्छेद 17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 2008 का 7253।

लैटर पेटेंट अपील संख्या 113/2005 में रांची, झारखंड के उच्च न्यायालय के 7.3.2006 के निर्णय और अंतिम आदेश से।

एम.पी. झा, राम एकबल रॉय और हर्षवर्धन झा अपीलार्थी के लिए।

ऐश्वर्या सिंह, आभास परिमल, अंबोज कुमार सिन्हा, रमेश एन. केसवानी, रामलाल रॉय, सुमिरा रहेजा (एम/एस.

केसवानी एंड कंपनी के लिए) और एजाज़ मकबूल उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा द्वारा दिया गया था।

मामला स्वीकार कर लिया गया

2. अपीलार्थी राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के तहत गठित एक निगम है (संक्षेप में "अधिनियम "). प्रतिवादी संख्या 1 का इरादा रांची शहर के औद्योगिक क्षेत्र, कोकर में एक कारखाना स्थापित करने का था। यह, 5.11.1976 को या लगभग, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, अपीलार्थी द्वारा रु. 3.36 लाख का ऋण मंजूर किया गया था।

3. पक्षों द्वारा और उनके बीच एक समझौता किया गया था, जिसके संदर्भ में, प्रतिवादी नं 1. अनुसूची 'क', 'ख' और 'ग' में वर्णित संपत्तियों को गिरवी रखा गया था - अपीलार्थी-निगम के पक्ष में, अर्थात् कोकर गाँव में 0.56 एकड़ भूमि के एक टुकड़े पर पट्टा अधिकार के रूप में।

4. बंधक के उक्त विलेख के संदर्भ में, वादी को चौदह किश्तों में ऋण की उपरोक्त राशि का परिसमापन करने की आवश्यकता थी। उस पर देय ब्याज हर छह महीने में

देय 14.25 प्रतिशत वार्षिक था। निर्विवाद रूप से, वादी ने रुपये की राशि वापस की। अपीलार्थी से प्राप्त कुल राशि में से 1,32,000/- रु. 3,34,300/-। वादी ने प्लॉट पर इमारतों के निर्माण करने का बाद मशीनरी स्थापित की। इस कारखाने ने नवंबर, 1978 के महीने से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, निश्चित रूप से कारखाने को मार्च, 1982 में किसी न किसी कारण से बंद कर दिया गया था।

5. इस आधार पर कि वादी विनिर्दिष्ट रीति से ऋण की रकम का संदाय करने में असफल रहा और/या उपेक्षा की, अधिनियम की धारा 29 और 30 के संदर्भ में कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा 7.12.1981 को या लगभग उसके आस-पास आरंभ की गई थी। कारखाने को बेचने के लिए विज्ञापन 16.12.1982 और 12.01.1983 को जारी किए गए थे। हालाँकि, उसके अनुसार और उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

6. उक्त संपत्तियों को श्री आत्मलाल अग्रवाल, यहाँ प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बेचने का निर्णय लिया गया था हालाँकि वादी को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। वादी के अनुसार, उक्त बिक्री गुपचुप तरीके से की गई थी। उक्त संपत्ति का निपटान करते समय, अपीलार्थी ने वादी के

हित को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। कारखाना परिसर को प्रत्यर्थी संख्या 2 जिसके लिए 16.02.1983 को एक सूची तैयार की गई थी जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"(क) प्लांट्स मशीनरी

(1) 312 (3-रोलर) रेमंड मिल प्लांट वीओरोप ड्राइव के लिए लेकिन मोटर के बिना और एयर-क्लासिफायर के साथ।

(2) जॉव क्रशर - बिना मोटर के

(3) ब्लोअर एक नंबर

(4) मोटर के बिना विघटनकर्ता 1 नंबर

(5) स्टार्टर और स्विच के साथ विद्युत स्थापना... "

7. निर्विवाद रूप से, उक्त कारखाने में, वादी के पास अन्य संपत्तियां थीं जो बंधक का विषय नहीं थीं। इसके अलावा यह विवाद में नहीं है कि वादी ने 1,60,000/- रुपये की राशि भारतीय स्टेट बैंक से यहाँ प्रतिवादी संख्या तीन से कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लिया था। तरल परिसंपत्तियों और स्टॉक सहित विभिन्न अचल संपत्तियों को इसके पक्ष में बंधक के रूप में रखा गया था। कथित तौर पर खरीदार ने उक्त सामग्रियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद वादी ने मनी सूट संख्या 9/1984 अधीनस्थ न्यायाधीश - IV रांची

के न्यायालय में, जिसमें मूल रूप से निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की गई थीः

“कि 1, 87, 635.24 रुपये (एक लाख आठ, सात हजार छह सौ पैंतीस और चौबीस पैसे) की राशि के भुगतान के लिए एक डिक्री। पास की जाए वाद की अनुसूची "क" में यथा विस्तृत हर्जाने के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 " के विरुद्ध।

8. हालाँकि, बाद में वाद में संशोधन किया गया और निम्नलिखित राहत जोड़ी गईः

" 1,86,934.46 रुपये की राशि के लिए एक डिक्री। प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध पारित किया जाए। वाद की अनुसूची "ख", "ग" और "घ" में विनिर्दिष्ट रूप से वादी को हुई गलत और जानबूझकर हानि के सम्बन्ध में।

9. अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित बयान में तर्क दिया कि उसने अधिनियम की धारा 29 और 30 के संदर्भ में अपनी शक्ति का ईमानदारी से प्रयोग किया था। इसने आगे तर्क दिया कि बैंक को नोटिस की सेवा के बावजूद फैक्टरी परिसर से जंगम संपत्ति को नहीं हटाया गया था, अपीलार्थी किसी प्रकार की वादी को हुई गलत और जानबूझकर हानि के सम्बन्ध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

10. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने पक्षकारों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दे तैयार किएः

“1. क्या वादी के पास मुकदमे के लिए कार्रवाई का कोई वैध कारण है?
2. क्या मुकदमा कानून के तहत सुनवाई योग्य है?
3. क्या मुकदमा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 46 (ख) के तहत गलत है?
4. क्या प्रतिवादियों ने उन चल संपत्तियों को ले लिया है और हटा दिया है जिन्हें निगम को अवैध रूप से और बिना कानूनी रूप से गिरवी नहीं रखा गया था?

5. क्या बिक्री जो यहाँ निगम प्रतिवादी संख्या 1 द्वार प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया गया सही और कानूनी है?
6. क्या वादी प्रतिवादियों द्वारा गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए और हर्जाने का हकदार है?

7. क्या वादी डिक्री के लिए हकदार है जैसा कि प्रार्थना की गई है?
8. वादी किस राहत या राहत, यदि कोई हो, का हकदार है?"

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित कियाः

"...शाखा प्रबंधक बी.बी. सिंह ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि अनुच्छेद 13 और 15 द्वारा सूची तैयार करने के समय वादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था और इसने प्रतिवादी संख्या 2 को सूची तैयार करने के समय प्रदीप मोदी की उपस्थिति के बारे में दिए गए बयान को झूठा साबित कर दिया। वादी और प्रतिवादियों के वृत्तचित्र और मौखिक साक्ष्य पूरी तरह से उस सूची जो साक्ष्य (एक्ज़िबिट) ख के रूप में बिल्कुल भी एक विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है और इसे सही और निष्पक्ष रूप से तैयार नहीं किया गया है और यह अधूरा है।
प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी की गिरवी रखी गई संपत्ति केवल साक्ष्य (एक्ज़िबिट) 7/4 के माध्यम से खरीदी थीऔर इसलिए प्रतिवादी नं 1 और प्रतिवादी संख्या 2 कच्चे माल, तैयार माल, पुर्जों आदि को अपने कब्जे में लेने में गलती

की दिनांक 16.2.83 को, जो प्रतिवादी सं. 2 को बिक्री करने का विषय नहीं था और उन खातों पर प्रतिवादी सं 1 और 2 उत्तरदायी हैं वादी को हर्जाने के रूप में भुगतान करने लिए जैसा की वाद में दावा किया गया था। इस प्रकार, मुद्दा संख्या 4 वादी के पक्ष में निर्णय लिया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध।"

इसके अलावा यह भी कहा गया थाः

"... वादी बैंक प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ डिक्री का हकदार नहीं है। वादी 13% प्रति वर्ष की दर से लंबित और भविष्य की प्राप्ति तक ब्याज का भी हकदार है। इस प्रकार, यह आदेश दिया जाता है कि इस मुकदमा में रुपए 1, 87, 635.24 (एक लाख आठ, सात हजार छह सौ पैंतीस और चौबीस पैसे) राहत संख्या क के दावे के लिए प्रतिवादी संख्या एक और और प्रतिवादी संख्या दो के खिलाफ लागत के साथ और 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ और भविष्य में प्राप्ति तक भुगतान करने का आदेश दिया जाए किया जाए वादी प्रतिवादी संख्या से और प्रतिवादी संख्या से संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से उपरोक्त राशि की वसूली कर सकता है।

मुकदमा रुपये 1, 85, 934.46 (एक अभाव छियासठ हजार नौ सौ चौंतीस और छियालिस पैसे मात्र) की राशि के लिए तय किया गया है। राहत सं. क-1, के लिए वाद को लड़ने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध लागत के साथ 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और भविष्य में प्राप्ति तक के लिए डिक्री की जाती है। राहत के दावे के लिए वाद सं. क-1 को प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ मुकदमा खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही को रद किया जाता है।"

11. उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। विवादित फैसले के कारण उक्त अपील को खारिज कर दिया।

12. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में विचार के लिए निम्नलिखित तीन बिंदु तैयार किएः "क्या अपीलार्थी ने उन चल संपत्तियों को हटा दिया जो निगम को अवैध रूप से या अनधिकृत रूप से गिरवी नहीं रखी गई थीं? क्या निगम द्वारा की गई बिक्री, प्रतिवादी-अपीलार्थी, प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में प्रामाणिक और कानूनी है, और क्या वादी-प्रतिवादी प्रतिवादियों द्वारा गिरवी रखी गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन करने के लिए हर्जाने का हकदार है? उच्च

न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी ने कारखाने का दरवाजा तोड़ा वादी के किसी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में। लेखों की सूची भी वादी के किसी भी प्रतिनिधि की उपस्थित के बिना तैयार की गई थी। मशीनरी की सूची जो कारखाना परिसर में थी, प्रतिवादी संख्या2 को सौंपीं गई थी। अपीलार्थी की इस दलील पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि कारखाना परिसर में कोई चल संपत्ति नहीं थी। निर्विवाद रूप से, वे संपत्तियाँ जो भारतीय स्टेट बैंक को बंधक रखी गई थीं, प्रत्यर्थी संख्या 3 भारतीय स्टेट बैंक को कोई जानकारी दिए बिना उठा लिया गया।

इस प्रकार, पहला बिंदु वादी - प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्धारित किया गया था। जहां तक बिंदुओं 2 और 3 की बात है तो संख्या 2 और 3 उच्च न्यायालय ने राय दीः

"31. एफ. ए. संख्या 22/199 दायर करने वाले अपीलार्थी आत्मा राम की ओर से एक याचिका दायर की गई है विद्वत न्यायालय के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध कि उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वह इस तथ्य के कारण हानि में है कि कारखाने की बिक्री से पूर्व, कारखाने के अधिग्रहण से ठीक पहले कारखाने से कुछ मशीनों को हटा

दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि -उसके द्वारा, उसने बिहार राज्य वित्तीय निगम रांची के शाखा प्रबंधक के साथ बातचीत की और उसके और शाखा प्रबंधक के बीच सहमत मूल्य पर कारखाने को खरीदने के लिए सहमत हो गया था और खरीद से पहले, यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसने कारखाने के परिसर से गुजरे बिना कारखाने का ख़रीदा। इसके अलावा, वह बिहार राज्य वित्तीय निगम और बिहार राज्य वित्तीय निगम के मुख्य कार्यालय में खोली गई निविदा में उपस्थित नहीं हुआ या भाग नहीं लिया, जब कोई निविदा दायर नहीं की गई थी, तो उसे फिर से निविदा जारी करनी चाहिए थी और शाखा प्रबंधक, प्रतिवादी संख्या 1 ने पटना के मुख्य कार्यालय से अनुमति प्राप्त की। बिक्री के अनुमोदन के लिए और समय के साथ, बिक्री को मंजूरी दी गई थी। निर्णय लेते समय मुद्दा संख्या 2, यह पाया गया कि बिहार राज्य वित्तीय निगम ने उचित तरीके से बिक्री का संचालन नहीं किया और उस कारखाने के लिए उचित मूल्य प्राप्त नहीं किया जिसका मूल्य प्रतिवादी संख्या 1 और, इसलिए, वादी द्वारा कारखाने के परिसर से सामानोंको हटाने का सवाल - प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, हालांकि एक प्रथम सुचना रिपोर्ट उस प्रभाव के लिए वादी-प्रतिवादी के

खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इस संबंध में एक मामला लंबित बताया गया है। लेकिन बिक्री जो प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी ने उचित तरीके से आचरण नहीं किया था और प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2, इसलिए सभी मानदंडों की अनदेखी करते हुए, बिक्री आयोजित की गई थी और इस तरह, दोनों प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 उत्तरदायी हैं, और इसलिए, नीचे दी गई विद्वत अदालत ने प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 - अपीलार्थी एफ.ए. संख्या 531/1993 वाद की अनुसूची क में वर्णित संपत्ति के नुकसान के लिए उत्तरदायी है। जहां तक राहत क-1 का संबंध था, प्रतिवादी संख्या 1 - अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराया गया है।

13. उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष इसके विरुद्ध दायर एक लेटर्स पेटेंट अपील को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

14. श्री. एम. पी. झा, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, यह तर्क देंगे कि निचली अदालतों ने विवादित निर्णय पारित करने में गंभीर अवैधता की क्योंकि वे अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 – बैंक को जारी

किए पत्रों पर संज्ञान नहीं नहीं लिया जो चल संपत्तियों को हड़पने के लिए लिखा गया उस दृष्टिकोण में अपीलार्थी को किसी भी लापरवाही का दोषी नहीं कहा जा सकता है।

विद्वान वकील ने दिखाया कि दो मामलों पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हर्जाने, जैसा कि वाद के प्रार्थना क और क-1 से दिखाई देगा, बनाए रखने योग्य नहीं हैं। वह, तथापि, न्यायसंगत रूप से स्वीकार करते हैं कि प्रार्थना क-1 के संबंध में पारित डिक्री से संतुष्ट है।

15. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वकील आक्षेपित निर्णय का समर्थन करेंगे।

16. अधिनियम की धारा 29 और 30 निम्नानुसार हैः

"29 चूक के मामले में वित्तीय निगम के अधिकार - (1) जहां कोई औद्योगिक संस्था, जो किसी समझौते के तहत वित्तीय निगम के दायित्व के तहत है, के संबंध में किसी भी ऋण या अग्रिम या उसकी किसी भी किस्त के पुनर्भुगतान में या अपने दायित्वों को पूरा करने में कोई चूक निगम द्वारा दी गई किसी गारंटी के लिए या अन्यथा वित्तीय निगम के साथ अपने समझौते की शर्तों

का पालन करने में विफल रहने पर, वित्तीय निगम को प्रबंधन या कब्जा या दोनों औद्योगिक सरोकारों को लेने का अधिकार होगा, साथ ही पट्टा या बिक्री के माध्यम से बी हस्तांतरण का अधिकार होगा और वित्तीय निगम को गिरवी रखी गई, गिरवी रखी गई, कल्पित या सौंपी गई संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) वित्तीय निगम द्वारा उप-धारा ग (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपत्ति का कोई अंतरण अंतरिती को अंतरित संपत्ति में या उसके सभी अधिकार इस प्रकार निहित करेगा मानो अंतरण संपत्ति के स्वामी द्वारा किया गया हो।

(3) वित्तीय निगम के पास निर्मित या पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पादित वस्तुओं के संबंध में वही अधिकार और शक्तियां होंगी जो उसके पास मूल वस्तुओं के संबंध में थीं।

(4) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी औद्योगिक संस्था के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है वहां सभी व्यय, प्रभार और व्यय, जो वित्तीय निगम की राय में उसके द्वारा संयोगवश उचित रूप से उपगत किए गए हैं,

औद्योगिक संस्था से वसूली योग्य होंगे और उसके द्वारा प्राप्त धन, इसके विपरीत किसी संविदा के अभाव में, प्रथमतः ऐसी लागतों, प्रभारों और व्यय के संदाय में और द्वितीयतः वित्तीय निगम को देय ऋण के निर्वहन में और इस प्रकार प्राप्त धन के शेष भाग का संदाय उसके हकदार व्यक्ति को किया जाएगा।

5) जहां वित्तीय निगम ने उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी औद्योगिक संस्था के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, वहां वित्तीय निगम को संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध वाद के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था का स्वामी समझा जाएगा और वह संस्था के नाम पर वाद दायर करेगा और वाद दायर करेगा।

30. सहमत अवधि से पहले पुनर्भुगतान के लिए बुलाने की शक्ति।

इसके विपरीत किसी समझौते में किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय निगम, लिखित सूचना द्वारा,-

(क) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक संस्था द्वारा ऋण या अग्रिम के लिए अपने आवेदन में

किसी सामग्री विशेष में झूठी या भ्रामक जानकारी दी गई थी; या

(ख) यदि औद्योगिक संस्था वित्तीय निगम के साथ अपने अनुबंध की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रही है, तो संबंधित वित्तीय निगम अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या ऋण या अग्रिम की कार्यवाहियों का भुगतान करने में असमर्थ है; या

(ग) यदि इस बात की उचित आशंका है कि उसके संबंध में औद्योगिक परिसमापन शुरू किया जा सकता है; या

(घ) यदि गिरवी रखी गई, गिरवी रखी गई, कल्पित या ऋण या अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में वित्तीय निगम को सौंपी गई संपत्ति का बीमा नहीं किया गया है और (वित्तीय निगम की संतुष्टि के लिए औद्योगिक कंपनी या मूल्य में इस हद तक अवमूल्यन किया गया है कि बोर्ड की संतुष्टि के लिए और प्रतिभूति दी जानी चाहिए और ऐसी प्रतिभूति नहीं दी गई है; या संयंत्र या अन्य उपकरण, चाहे

(ङ) बोर्ड की अनुमति के बिना, किसी भी प्रतिभूति मशीनरी को औद्योगिक निगम द्वारा बिना किसी कारण के हटा दिया गया हो या हटा दिया गया हो, वित्तीय निगम के हितों की रक्षा करने के लिए यदि आवश्यक हो।

17. उपर्युक्त उपबंधों के एक अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निगम में निहित वैधानिक शक्ति का प्रयोग केवल उन संपत्तियों के संबंध में किया जाना चाहिए जिन्हें गिरवी रखा गया था। इस मामले का यह पहलू रहा है ओर्मी टेक्सटाइल्स और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 2008 (5) एससीसी 194, में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया, अभिनिर्धारित करते हुएः

“15. अधिनियम की धारा 29 को लागू करने के उद्देश्य से, उधारकर्ता का निगम के लिए दायित्व होना चाहिए एक समझौता के द्वारा। इसे किसी भी ऋण या अग्रिम आदि के पुनर्भुगतान में चूक का मामला होना चाहिए। ऐसी स्थिति में निगम को अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन या कब्जा या दोनों औद्योगिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार होगा। यह शक्ति पट्टा या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण करने और निगम को गिरवी रखी

गई, गिरवी रखी गई, कल्पित या सौंपी गई संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकार के अतिरिक्त है। हालांकि, पट्टे या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार एक स्वतंत्र अधिकार नहीं है। केवल डिफ़ॉल्ट के मामले में, इस तरह के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिनियम की धारा 29 के दो भागों में निहित शक्तियां अलग और विशिष्ट हैं। प्रबंधन को संभालने की शक्ति का प्रयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब कंपनी चल रही होती है। लेकिन, जब संपत्ति को एकतरफा रूप से बेचने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो उसका बंधक संपत्ति के साथ संबंध होना चाहिए। बिक्री की शक्ति को अलगाव में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह बंधक की गई संपत्ति को भी प्राप्त कर सकता है जिसका अर्थ होगा कि जब कोई संपत्ति बेची गई थी, तो केवल बंधक की गई संपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी अन्य संपत्ति को जो बंधक का विषय नहीं था। क्या संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में भी बंधक द्वारा स्थानांतरित संपत्ति है जो बंधक का विषय था और किसी अन्य नहीं है। प्रबंधन या कब्जा लेने की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है। जैसे ही और जब ऋण की प्राप्ति होगी, निगम संपत्ति का प्रबंधन या कब्जा, जैसा भी

मामला हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान को वापस सौंपने के लिए बाध्य होगा।

16. एक बंधकधारक को अनुबंध के तहत भी संपत्ति बेचने का अधिकार हो सकता है। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ होना चाहिए कि बेची जाने वाली संपत्ति वही है जिस पर उसका अधिकार, अधिकार और ब्याज है। बिना किसी अधिकार के बिक्री जी शून्य होगी।

17. अधिनियम के प्रावधानों के उचित निर्माण के लिए, हम इसकी धारा 31 के प्रावधानों को नोटिस कर सकते हैं। यह एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है। जबकि धारा 29 संपत्ति को एकतरफा रूप से बेचने की शक्ति प्रदान करती है, धारा 31 अन्य बातों के साथ-साथ उसी शक्ति के लिए केवल अदालत का हस्तक्षेप का प्रयोग कर सकती है।

18 अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिक्री के आदेश के लिए जिला न्यायाधीश की अधिकारिता का उपयोग किया जा सकता है। निगम के पक्ष में गिरवी या आवंटित संपत्ति। इसके खंड (ख) में औद्योगिक संस्था के प्रबंधन को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 31

की उपधारा (1) के खंड (कक) और (ग) में अतिरिक्त उपायों का प्रावधान है। जब अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1क) में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है। एक अतिरिक्त उपाय अधिनियम की धारा 32 छ के संदर्भ में प्रदान किया गया है।"

18. मामले के उस दृष्टिकोण में, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी को ऐसी कोई संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं था जो बंधक विलेख की विषय वस्तु न हो। उस ओर से की गई किसी भी कार्रवाई को पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाना चाहिए। इसलिए, अपीलार्थी था। जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा राय दी गई थी, नुकसान के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

19. हम यह भी देख सकते हैं कि अपीलार्थी ने हमारे समक्ष संशोधित वाद प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि प्रार्थना क कअनुसूची क से संबंधित है, प्रार्थना क-1 अनुसूची ख, ग और से संबंधित है। हमें इस बारे में सूचित नहीं किया

गया है कि ये अनुसूचियाँ किस बारे में थीं। हालाँकि, शिकायत के साथ संलग्न अनुसूची 'क़' निम्नानुसार हैः

“अनुसूची क

1. जमा किए गए स्टॉक स्टेटमेंट के अनुसार रुपए 1, 30, 161.64 भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा न्यायालय परिसर, रांची, दिनांक 31.3.1982

2. कोयले की लागत 10,808 मीट्रिक टन तार रुपए 45, 393.60; पिच @रु 4200/- पीएमटी

3. पिल्ला मिटी के 190 थैलों की कीमत रुपए 3, 800.00 @ रुपए 20/- प्रति बैग।

4. ग्रेफाइट की लागत 1.5 एमटी रुपए 1, 500.00/- पाउडर @Rs.1,000/- /- पीएमटी

5. 4000 की लागत। प्रथम श्रेणी ईंटें रुपए 1, 280.00 @ रुपए 320/- 1000 नंबर।

6. चैनलों के कोणों आदि की लागत रुपए 2, 500.00. 500 किलोग्राम @ रु. 5, 000/- पीएमटी

7. 1.5 मीट्रिक टन लोहे के नाखूनों की लागत रुपए 3, 000.00 @2,000/- पीएमटी) कुलः रुपए 1, 87, 635.24 पी "

20. बार में यह स्वीकार किया जाता है कि उपरोक्त चल संपत्तियां प्रत्यर्थी सं. 3. के पास गिरवी रखी गई थी। इसके अलावा इस बात से इनकार या विवाद नहीं किया गया है कि प्रतिवादी नं-3-बैंक ने अपने बकाये की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। संभवतः, यह तत्काल मामले के लंबित होने के कारण ऐसा नहीं कर सका और वादी द्वारा किए गए दावों में से एक को भी बैंक के खिलाफ निर्देशित किया गया था।

21. इसलिए, हम पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की दृष्टि से यह राय रखते हैं कि बैंक को कल्पित चल संपत्तियों की प्राप्ति नहीं की गई है और चूंकि इसे हटाने के लिए यह अनुमत था, इसलिए प्रार्थना 'क' के संबंध में डिक्रीटल राशि को भारतीय स्टेट बैंक को देय माना जाना चाहिए- 'प्रत्यर्थी सं. 3. हम उसी के अनुसार निर्देश देते हैं। डिक्रीटल राशि का भुगतान 'अपीलार्थी' द्वारा पुनरावेदन सं. 3 के रूप में ब्याज के साथ जो डिक्री को निष्पादित करने के लिए बैंक

के लिए खुला होगा विफल होने की तारीख से छह महीने के भीतर नीचे की अदालतों द्वारा जैसा निर्देशित किया गया है।

22. अपील को उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज कर दिया जाता है। तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।